शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-46 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 20-27 नवम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

क्या मुख्यमंत्री कर्ज के आंकड़े को लेकर झूठ बोल रहे है?

क्या आरटीआई दस्तावेज मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाया गया होगा?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद अब तक कितना कर्ज ले चुकी है इस पर भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एकदम आमने-सामने आ गये हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिन्दल ने एक पत्रकार वार्ता में आरटीआई के माध्यम से जुटायी गयी जानकारी के आधार पर आरोप लगाया है कि यह सरकार दिसम्बर 2022 से अक्तूबर 2023 तक 10300 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस कर्ज के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमों ने भी 1000 करोड़ का कर्ज लिया है। सरकार ने अभी 800 करोड़ का और कर्ज लिया है। इस तरह सरकार कुल मिलाकर 12000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। जबकि इस सरकार में कोई नये संस्थान नहीं खोले हैं बल्कि भाजपा शासन में खोले गये संस्थानो को बन्द किया है। डॉ. बिन्दल ने प्रैस वार्ता में आरटीआई का दस्तावेज भी जारी किया है।

डॉ. बिन्दल की इस प्रैस वार्ता के बाद सूचना एवंम् जनसंपर्क विभाग ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक ब्यान जारी किया है। इस ब्यान में मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष के आरोप का कोई जिक्र किये बिना यह कहा है कि उनकी सरकार ने केवल 4100 करोड़ का कर्ज लिया है। इस ब्यान में मुख्यमंत्री ने पूर्व जयराम सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह दावा भी किया है कि उनकी सरकार ने प्रदेश के राजस्व में 1100 करोड़ की वृद्धि की है। यदि आपदा न आती तो यह राजस्व 500 करोड़ और बढ़

जाता। मुख्यमंत्री के इस ब्यान के साथ कोई दस्तावेज जारी नहीं किये गये है। सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालने के बाद डीजल और अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में बढ़ौतरी की है उसके परिप्रेक्ष में राजस्व में बढौतरी होना स्वभाविक है। लेकिन इन दोनों शीर्ष नेताओं के इस तरह आमने-सामने खड़े होने से आम जनता में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आरटीआई में कोई गलत जानकारी तो नहीं जा सकती। ऐसे में यह कर्ज कहां खर्च हुआ है यह जिज्ञासा एक बड़ा सवाल बन कर खड़ा हो गया है। क्योंकि दोनों नेताओं के ब्यानों के बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि मुख्यमंत्री कर्ज के आंकड़ों को छुपा क्यों रहे है। जबकि आरटीआई में मिली जानकारी और सूचना एवंम् जनसंपर्क विभाग का नोट दोनों एक ही प्रशासन के माध्यम से आये हैं।

RTI Matter

No: Fin-2-B (9)-1/2008-III
Government of Himachal Pradesh
Finance (W&M) Department

From

The PIO-cum-Section Officer (Finance-B),
H.P Secretariat, Shimla-02

To

Sh. Karan Nanda,
Mall Road, Shimla-171001

Dated: Shimla-02, the 31-10-2023

Subject: **Regarding Information under RTI Act, 2005**

Sir,

Please refer to your application dated 19.10.2023 under the Transaction No. A23J223381 received in this office dated 20.10.2023 on the subject cited above and to inform you that the State Government has taken a loan of ₹ 10,300 Crore since December, 2022 to October, 2023.

If you are not satisfied with the above, you have a right to prefer an appeal to the First Appellate Authority i.e Under Secretary/Officer-on-Special Duty (Ways & Means) to the Government of Himachal Pradesh within a period of 30 days.

Yours faithfully,

PIO-cum-Section Officer (Finance-B),
H.P. Secretariat, Shimla-02

स्मरणीय है कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब जयराम सरकार पर प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फसाने का आरोप लगाया जाता था लेकिन आज कांग्रेस की सरकार तो कर्ज का आंकड़ा ही प्रदेश की जनता से छुपाने के कगार पर आ गई है। जयराम सरकार से विरासत में 92000 हजार करोड़ की देन दारी मिलने की बात वितिय श्वेत पत्र में दिखाई गयी है। उस समय कर्मचारियों के कुल सृजित पदों में से 70000 पद खाली थे यह जानकारी हर्षवर्धन कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से सामने रखी गयी है। यह पद आज भी खाली ही है। बल्कि इस दौरान कुछ विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारियों की छंटनी तक कर दी गयी है। संशोधित वेतनमानों का बकाया यह सरकार भी नहीं दे पायी है। इस संद्धर्भ में आये दर्जनों अदालती फैसलों पर अमल नहीं हो पाया। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त भी यह सरकार अभी तक नहीं दे पायी है।

इस वस्तु स्थिति में आरटीआई के सामने आयी कर्ज

की जानकारी और उस पर मुख्यमंत्री के अपरोक्ष इन्कार के बाद यह सवाल हो गया है कि आखिर कर्ज के आंकड़े को छुपाया क्यों जा रहा है? जब आपदा के नाम पर विभागीय खर्चो में कटौती कर दी गयी है और कोई नये संस्थान खोले नहीं जा रहे हैं। फिर राजस्व में भी वृद्धि होने का दावा किया जा रहा है तो यह कर्ज खर्च कहां किया जा रहा है। जब आरटीआई का दस्तावेज सामने है तो फिर उसे झुठलाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? क्या प्रशासन मुख्यमंत्री को सही जानकारी ही उपलब्ध नहीं करवा रहा है? यह तय है कि जब सरकार पर तथ्यों को छुपाने के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं तो उसके परिणाम घातक हो जाते है।

मेले तथा उत्सव प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रतीकःराज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल ने शिव प्रताप शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की और कहा कि मेले तथा उत्सव प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपनी इस संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। खुशहाली के लिए आगे बढ़ने के साथ-साथ संस्कृति का संरक्षण भी आवश्यक है।

राज्यपाल ने यह जानकारी सिरमौर के अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले के समापन समारोह के अवसर पर जनसमूह को सम्बोधित करते हुए दी। लेडी गवर्नर तथा राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा, संस्कृति तथा खुशहाली के लिए जाना जाता है लेकिन नशे की प्रवृत्ति राज्य की समृद्धि पर ग्रहण लगा रही है। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ मिल-जुल कर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नशे का अंत केवल मौत है तथा इस बुराई से प्रदेश को बचाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि सिरमौर कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जिले को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने जिला प्रशासन को श्री रेणुका जी झील के सौंदर्यकरण के लिए कहा।

शुक्ल ने कहा कि रेणुका जी मेला माता रेणुका जी के प्रति भगवान परशुराम की श्रद्धा तथा भक्ति का प्रतीक है तथा यह मेला भारतीय समाज के उच्च मूल्यों को संरक्षित करने में अहम् भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले तथा उत्सव प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के द्योतक हैं और इन्हें हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने मेले के सफल आयोजन में सभी के योगदान के लिए बधाई दी तथा कहा कि माता रेणुका जी का अपना एक धार्मिक महत्व है। इस मेले में प्रदेश तथा अन्य राज्यों से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने भगवान परशुराम जी मंदिर तथा माता रेणुका जी मंदिर में पूजा-अर्चना की और देव विदाई शोभा यात्रा में भी भाग लिया।

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गुरु नानक जयन्ती पर बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरु नानक जयन्ती के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर सिक्ख समुदाय के लोगों को बधाई दी है।

राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि गुरु पर्व सिक्खों का पवित्र त्यौहार है, जिसे सिक्खों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि गुरूजी की शिक्षाओं का अनुसरण कर हम शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बधाई संदेश में कहा कि गुरु नानक देव जी ने प्रेम, शांति तथा साम्प्रदायिक सद्भाव का सन्देश दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने विश्व बन्धुत्व पर बल दिया और उनकी शिक्षाएं मौजूदा परिस्थितयों में और भी प्रासंगिक हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक विजेता निषाद की सराहना की

शिमला/शैल। चीन के हांगझोऊ में आयोजित एशियन पैरा गेम्स-2023 में ऊंची कूद के स्वर्ण पदक विजेता निषाद कुमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए निषाद कुमार की सराहना की।

सुक्खू ने कहा कि निषाद कुमार सभी विशेषकर प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। देश व प्रदेश का नाम रौशन करने के लिए निषाद कुमार की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं।

प्रतियोगिता के दौरान निषाद कुमार द्वारा प्रदर्शित लग्न तथा मेहनत युवाओं को सफल बनने की सीख देती है। उन्होंने जिस प्रकार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से शारीरिक अक्षमता व चुनौतियों का सामना किया है, वह सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने निषाद कुमार की प्रतिभा पर भरोसा जताते हुए भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में उनकी सफलता की कामना की।

विधायक चिंतपूर्णी सुदर्शन बबलू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हाल ही में हिमाचल में आई आपदा के समय सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने आपदा राहत कार्यों में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश आपदा से उभरकर पुनः विकास पथ पर अग्रसर हुआ है।

राज्यपाल सोलन में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

राज्यपाल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सोलन जिला में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से प्रगति पथ को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि जिले का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र प्रदेश का औद्योगिक एवं फार्मा हब है। यहां उत्पादित की जा रही दवाओं की गुणवत्ता विश्व स्तरीय मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। उन्होंने उपायुक्त सोलन को प्रदेश के इस फार्मा हब में उत्पादित की जा रही दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण का अनुश्रवण करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जिला में आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को बेहतर आवागमन के लिए सुचारू बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों से सोलन जिला भी लाभान्वित होता है और इस दिशा में सड़कों का रख-रखाव महत्वपूर्ण है।

शुक्ल ने निर्देश दिए कि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्य समयबद्ध पूर्ण किए जाएं ताकि केन्द्र सरकार से धनराशि समय पर प्राप्त होती रहे। उन्होंने जिला में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की जिला स्तर पर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

समीक्षा बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन जिला में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 90 प्रतिशत से अधिक के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। समीक्षा बैठक में आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, तपेदिक मुक्त भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, विभिन्न कृषि योजनाओं, ई-राष्ट्रीय कृषि व्यापार योजना, विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कल्याण योजनाओं, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर सारगर्भित चर्चा की गई।

इस अवसर पर, सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिला स्तर पर कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रगति की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विभिन्न निर्देशों पर पूर्ण अमल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने महिला कबड्डी टीम को किया सम्मानित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय महिला कबड्डी की स्वर्ण पदक विजेता टीम को सम्मानित किया। इस कबड्डी टीम ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसिज कबड्डी टूर्नामेंट 2023-24 में स्वर्ण पदक जीता है।

मुख्यमंत्री ने कबड्डी टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि उनके प्रदर्शन से प्रदेश के अन्य युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

कुमारी कृष्णा ठाकुर की कप्तानी में इस टीम ने पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है।

लाहौल स्पीति ज़िले के निवासियों ने 29 लाख रुपए आपदा राहत कोष में भेंट किए

शिमला/शैल। लाहौल स्पीति जिले के कर्मचारियों , किसानों, पंचायती राज संस्थाओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों तथा अन्य निवासियों ने सेव लाहौल स्पीति स्वयंसेवी सोसाइटी के माध्यम से प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 29 लाख रुपए के चेक भेंट किये । इसके अतिरिक्त लाहौल स्पीति ज़िले के निवासियों तथा अन्य जिलों के लोगों से 9 लाख रुपए का अंशदान एकत्र कर मुख्यमंत्री राहत कोष में भी जमा किया है।

मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए महत्वपूर्ण हैं।

इस अवसर पर सेव लाहौल स्पीति सोसाइटी के अध्यक्ष तथा पूर्व डीएसपी प्रेम कटोच के साथ संस्था के अन्य सदस्य, केंद्र सरकार के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सुंदर ठाकुर, पूर्व वरिष्ठ बैंक अधिकारी टशी छेरिंग, वर्तमान में आईटीबीपी में डीआई जी के पद पर कार्यरत प्रेमसिंह और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को जीवन में आत्मसात करें: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर

गुरूद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा में शीश नवाया। इस अवसर पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को सिरोपा भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव जयंती पर लोगों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि गुरु नानक देव जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी द्वारा दी गई शिक्षाओं का वर्तमान में भी विशेष महत्व है और लोगों से आग्रह किया कि इन शिक्षाओं को अपने जीवन में आत्मसात करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म के संस्थापक व पहले सिख गुरु गुरुनानक देव जी समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए जीवन भर अथक प्रयास करते रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और कहा कि प्रदेश सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना आरम्भ की है जिसके तहत विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इस अवसर पर मीडिया कर्मियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उपयुक्त समय पर कांग्रेस पार्टी के उच्च पदाधिकारियों से परामर्श के उपरांत मंत्रिमण्डल के विस्तार का निर्णय लेंगे।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा और सुदर्शन बबलू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

सड़क निर्माण में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश:विक्रमादित्य

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के अधिकारियों को सड़कों के निर्माण में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। वह निर्माण भवन, शिमला में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा परिवहन विभाग और द इंस्टीटयूशन ऑफ इंजीनियर्स, हिमाचल राज्य केन्द्र के सहयोग से सड़क सुरक्षा विषय पर विशेष जागरूकता अभियान के तहत आयोजित सेमिनार को सम्बोधित कर रहे थे।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा 'हमारा दायित्व सड़क निर्माण तक ही सीमित नहीं है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत कार्य निष्पादन में अभियांत्रिकी का सही उपयोग करना भी हमारा

दायित्व है'। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत सभी हितधारक विभागों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को दुर्घटना संभावित स्थलों व ब्लैक स्पॉट का अध्ययन कर उनका उचित समाधान करने के निर्देश भी दिए।

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा अभियांत्रिकी को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने सड़क सुरक्षा को योजना का अभिन्न अंग बनाने, सुरक्षा का नियमित ऑडिट करने और आटिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम मेधा) के उपयोग के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यात्रियों व पर्यटकों को बेहतरीन सम्पर्क सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसी ध्येय के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने केस स्टडी कर श्रेष्ठ तकनीकों को अपनाने के लिए भी कहा।

उन्होंने कहा कि सड़कें पहाड़ी राज्य की भाग्य रेखाएं हैं। प्रदेश के गठन के समय सड़कों की लम्बाई बहुत सीमित थी। वर्तमान में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया गया है। दूर-दराज के क्षेत्रों तक भी सड़क एवं सम्पर्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पर्यटन राज्य होने के नाते प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण नितान्त आवश्यक है। उन्होंने अभियन्ताओं से सड़क सुरक्षा के मध्यनज़र अपना श्रेष्ठ योगदान देने का भी आहवान किया।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक सामाजिक पहलू भी है। यात्र के दौरान वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वाले व्यक्तियों को भी सुरक्षा के दृष्टिगत जागरूक किया जाना चाहिए। इस संबंध में जागरूकता अभियान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता अजय गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश सड़कों को स्तरोन्नत किया गया है। विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत अभियांत्रिकी पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर पंजाब अभियांत्रिकी महाविद्यालय चण्डीगढ़ के विभागाध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यूआईटी के निदेशक प्रो. ए.जे. सिंह, द इंस्टीटयूटन ऑफ इंजीनियर्स, हिमाचल केन्द्र के अध्यक्ष वी.एम. जोशी, अतिरिक्त आयुक्त परिवहन नरेश ठाकुर ने भी सड़क सुरक्षा विषय पर व्याख्यान दिए।

सेमिनार में सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों और प्रदेशभर के विभिन्न अभियन्ताओं ने भाग लिया।

नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कृषि क्षेत्र में खुलेंगे सम्पन्नता के द्वार:चन्द्र कुमार

शिमला/शैल। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की अधिकतम

आबादी नियमित आय के लिए खेती पर निर्भर है। आज के समय में कृषि सबसे तेजी से बढ़ते व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में उभर रही है। युवा पीढ़ी को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि इसकी आधारिक संरचना का विकास आधुनिक समय की मांग अनुसार किया जाए। यह बात कृषि मंत्री प्रो.चंद्र कुमार ने कृषि विभाग द्वारा 'कृषि अवसंरचना कोष' योजना पर आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव में बतौर मुख्यातिथि कही।

उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से प्रदेश में कृषि सम्बन्धी अधोसंरचना के विकास के लिए अधिकतम 9 प्रतिशत की ब्याज दर पर दो करोड़ तक के ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज छूट दी जाती है। उन्होंने कहा कि कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी, मशीनरी, अनुसंधान व उन्नत बीज का समावेश कर किसानों को लाभान्वित करने में वांछित सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पूंजीगत निवेश की अपार संभावनाएं हैं। यहां पर कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग प्लांट्स, सॉर्टिंग व ग्रेडिंग यूनिट्स, पैकेजिंग यूनिट्स, वेयरहाउस और सप्लाई चेन सम्बन्धी अधोसंरचना आदि क्षेत्रों में निवेश कर लाभ अर्जित किया जा सकता है। इससे प्रदेश में रोजगार एवं स्वरोजगार के हजारों अवसर भी सृजित होंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से प्रदान की जा रही सुविधाओं के दायरे में विविधता लाने के साथ-साथ लाभार्थियों तक इसके लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ एकल खिड़की मंजूरी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 'कृषि अवसंरचना कोष' सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ छोटे, जरूरतमंद एवं गरीब किसान को आसानी से प्राप्त हो। इसके लिए योजना के लाभ घर-द्वार पर उपलब्ध किये जाने चाहिए। इससे किसान के समय एवं धन की बचत होगी। उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष के तहत परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है ताकि इसके व्यावहारिक लाभ लोगों को मिल सके। उन्होंने प्रदेश में सिंचाई अवसंरचना के निर्माण पर भी बल दिया और कहा कि एक मजबूत और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था के विकास से ही कृषि क्षेत्र में सम्पन्नता लायी जा सकती है।

कृषि मंत्री ने कहा की राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि उनका संपन्न एवं सुनहरा भविष्य सुनिश्चित हो।

इस अवसर पर निदेशक, कृषि अवसंरचना कोष, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के.आर. मीणा ने राज्य सरकार का इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ वर्ष, 2020 में इस योजना की शुरुआत की गयी थी। इस योजना के तहत प्रदान किये जा रहे लाभों को केंद्र और राज्य सरकारों की उपदान या सबवेंशन की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है।

कृषि अवसंरचना कोष के तहत हिमाचल प्रदेश को 925 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। अब तक कुल 599 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 438 आवेदनों को सत्यापित किया जा चुका है। इनमें से 221 करोड़ रुपये के 324 आवेदनों को विभिन्न बैंको से स्वीकृति मिल चुकी है और 67 करोड़ रुपये लाभार्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं।

इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव सी. पालरासु, संयुक्त निदेशक, रघबीर सिंह व जीत सिंह ठाकुर, नाबार्ड डीजीएम संजीव शर्मा, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक प्रदीप केसरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग का प्रदेशव्यापी अभियान

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ व्यापक अभियान आरम्भ किया है। इसके तहत विभाग द्वारा सूचना तंत्र को मजबूत बनाने के साथ-साथ संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त डॉ. यूनुस ने बताया कि विभाग ने जिला सिरमौर के पावंटा साहिब के नजदीक टोका नगला नामक स्थान पर घने जंगलों में अवैध रूप से चलाई जा रही तीन भट्टियों पर कारवाई कर 14 हजार 500 लीटर लाहन बरामद कर नष्ट की। इसकी अनुमानित लागत 4.35 लाख रुपये आंकी गई है। यह कारवाई सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी संदीप अत्री के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा की गई।

आयुक्त ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा मण्डी जिला में भी अंग्रेजी शराब व बीयर की 115 पेटियां जब्त की गई हैं जोकि चण्डीगढ़ में विक्रय के लिए बनाई गई थीं। उन्होंने बताया कि राज्य में अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए 24 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है ताकि अवैध शराब के साथ-साथ कर चोरी के मामलों पर जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित की जा सके। विभाग द्वारा इस वर्ष अभी तक 309 मामलों में कारवाई कर 1,08,698 लीटर अवैध शराब (लाहन) जब्त की गई है।

डॉ. यूनुस ने नागरिकों से आग्रह किया कि अवैध शराब तथा कर चोरी के मामले संज्ञान में आने पर टॉल फ्री नम्बर 1800-180-8060 तथा व्हाट्सएप नम्बर 94183-31426 पर जानकारी साझा करें ताकि इस अभियान को सफल बनाया जा सके। विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ कारवाई सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घण्टे सक्रिय कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

बह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है वह हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

व्यवस्था परिवर्तन को परिभाषित करना होगा

सुक्खू सरकार को सत्ता संभाले एक वर्ष होने जा रहा है। इतना समय सरकार के कामकाज की धुरी का आकलन करने के लिये पर्याप्त हो जाता है। भले ही उसके परिणामों का आकलन चुनावी वर्ष में ही होता है। परन्तु एक वर्ष में यह स्पष्ट हो जाता है कि अंत तक पहुंचते पहुंचते यह सरकार कहां आकर खड़ी होगी। केन्द्र की मोदी सरकार 2014 में जिन तेवरों के साथ सत्ता में आयी थी वह आज पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में कहां जाकर पहुंच गयी है यह सबके सामने आ गया है। जो प्रश्न आज मोदी सरकार को लेकर उठ रहे हैं कुछ समय पहले तक उनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन जो लोग यह जानते थे कि भाजपा संघ की राजनीतिक इकाई से ज्यादा कुछ नहीं है और संघ परिवार अनुषांगिक संगठनों और उनकी विचारधारा पर बराबर नजर रख रहे थे वह स्पष्ट थे कि मोदी सरकार एक समय ऐसे प्रश्नों से घिर जायेगी। जहां उसका भविष्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो जायेगा। मोदी सरकार का आकलन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होना था इसलिये उसमें इतना समय लगना स्वभाविक था। परन्तु किसी राज्य सरकार का यह आकलन एक वर्ष के कार्यकाल में ही हो जाता है।

इस गणित में जब सुक्खू सरकार के जमा घटाव का लेखा-जोखा देखा जाये तो पहला बिन्दु आता है सरकार का व्यवस्था परिवर्तन का नीति वाक्य। लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन को आज तक परिभाषित नहीं किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्ता परिवर्तन के बाद भी उनके स्थानों से न बदलने को ही व्यवस्था परिवर्तन मान लिया गया। प्रदेश की जनता को वित्तीय स्थिति को श्रीलंका जैसे हालात तक पहुंचाने की चेतावनी देकर सेवाओं और वस्तुओं के दाम बढ़ाने का रास्ता अपना लिया गया। पिछली सरकार पर प्रदेश को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसाने का तमगा देकर स्वयं प्रतिमाह एक हजार करोड़ का कर्ज लेने का फतवा ले लिया। प्रदेश के युवाओं को प्रतिवर्ष एक लाख नौकरियां देने का वायदा करके उस संस्थान को ही भंग कर दिया जिसके जिम्मे नौकरियां देने की प्रक्रिया को अंजाम देने का काम था। मुफ्त बिजली देने के वायदे पर पहले एक हजार मैगावाट का उत्पादन करने का लक्ष्य तय कर लिया जो शायद पांच वर्षो में ही पूरा हो पायेगा। शिक्षा जैसे विभाग में जहां सरकार की अपनी ही रिपोर्ट के मुताबिक बीस हजार अध्यापकों के पद खाली हैं उस विभाग में अंग्रेजी माध्यम से अगले सत्र से शिक्षण देने की घोषणा करना कई सवाल खड़े करता है।

यह आरोप खुले तौर पर लगने शुरू हो गये हैं कि अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार पर जब मित्रों की सरकार होने का आरोप लगना शुरू हो जाये तो ऐसी सरकार से आम आदमी की अपेक्षाओं का अन्त क्या होगा इसका अनुमान और आकलन कोई कठिन काम नहीं रह जाता है। जब सरकार दस्तावेजी साक्ष्यों को भी झुठलाने पर आ जाये तो उस सरकार को लेकर किस तरह की जनधारना बनेगी इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं रह जाता है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के बाद भी जो सरकार संवद्ध तन्त्र के प्रति कोई कठोर कदम न उठा पाये उसके श्वेत पत्र की विश्वसनीयता कितनी रह पायेगी यह सोचना है। व्यवस्था परिवर्तन को परिभाषित करना बहुत आवश्यक है क्योंकि अधिकारियों का स्थानांतरण न करना पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था को ही संरक्षण देना बन जाता है। यदि यह सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नीति वाक्य पर निष्पक्षता से पुनर्विचार नहीं करती है तो आने वाले चुनाव की परीक्षा में सफल होना कठिन होगा।

कट्टरता को दूर करने का एकमात्र औजार है शिक्षा, बिहार के इस शख्स ने वर्षों पहले किया प्रयोग

गौतम चौधरी

मानसिक चेतना को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका अहम होती है। यही नहीं यह किसी प्रकार के वैचारिक और सांप्रदायिक कट्टरपंथ को भी सीमित करता है। वैसे तो दुनिया भर में इसके प्रयोग देखे जा सकते हैं लेकिन बिहार के एक शख्स ने इसे साबित कर दिखाया है।

आज जब मानव जाति मजबूती से अंतरिक्ष में अपना पांव जमा रहा है और दुनिया के कई रहस्यों का उद्भेदन कर रहा है तो उसके सामने कई चुनौतियां भी उपस्थित हो रही है। उन चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती धार्मिक व वैचारिक कट्टरता है। कट्टरपंथ और उग्रवाद की चिंताओं से घिरी दुनिया में डॉ. प्रोफेसर कासिम अहसन वारसी एक ज्योति पुंज के समान दिखाई देते हैं, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सांप्रदायिक कट्टरता को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। डॉ. वारसी की कहानी, अनगिनत लोगों के साथ, इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि शिक्षा कैसे आशा की किरण बन कर व्यक्ति को कट्टरपंथ से छुटकारा दिलाता है। साथ ही जीवन को सशक्त बनाने में मददगार साबित होता है।

डॉ. वारसी का जन्म 10 नवंबर, 1933 को बिहार के अरवल जिले में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो ज्ञान और संस्कृति को महत्व देता था। उनके पिता, शाह मुहम्मद जकी अहसन ने छोटी उम्र से ही उनमें शिक्षा के प्रति प्रेम पैदा कर दिया। प्रारम्भ में डॉ. वारसी ने मौलवी सैय्यद अब्दुल माजिद के मार्गदर्शन में घर पर ही धार्मिक और प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें कुरान की पढ़ाई के साथ-साथ अरबी, फारसी और उर्दू भी शामिल थे। डॉ. वारसी के जीवन में उनके पिता की मृत्यु के साथ ही त्रासदी शुरू हो गई। हालांकि, उनकी मां ने पढ़ाई में कभी कोताही नहीं की और उनके जीवन को सजाने व सराहने का बीड़ा उठाया। उनके बेटे की शिक्षा जारी रखी। उन्होंने उसे पास के एक स्कूल में दाखिला दिलाया, उसके बाद पटना मुस्लिम हाई स्कूल में दाखिला कराया, जहां उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। उनकी शैक्षिक यात्रा अब भी चल रही थी। इस दौरान उन्होंने पटना के बी.एन कॉलेज बी.ए. और बाद में पटना विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एम.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की।

डॉ. वारसी की ज्ञान के प्रति अतृप्त प्यास ने उन्हें दूसरी बार एम.ए. करने के लिए प्रेरित किया। इस बार उर्दू से उन्होंने स्नातकोत्तर उत्तीर्ण किया। उसके बाद उर्दू में ही उन्होंने पीएच.डी. भी कर ली। वारसी यहीं नहीं रूके। डॉ. वारसी के लिए शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास के बारे में नहीं थी। यह उनके समुदाय और उसके जैसे अन्य लोगों के उत्थान के बारे में था। उनका मानना था कि शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है, व्यक्तियों को सशक्त बना सकती है और समाज को बदल सकती है। साथ ही मानव को सहिष्णु बनाती है। उनका दृष्टिकोण कक्षा से परे तक फैला हुआ था और उन्होंने उन लोगों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम किया, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।

20वीं सदी के बिहार में, जहां मुसलमानों के लिए शैक्षिक अवसर सीमित थे, डॉ. वारसी ने इस अंतर को पाटने के लिए स्कूलों की स्थापना की। प्रसिद्ध शिक्षक डॉ. जाकिर हुसैन से प्रेरित होकर, उन्होंने वंचितों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पटना में सुल्तान गंज स्कूल खोला, जिसे अब डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पटना के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में एमआई हैट उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल ने बिहारी मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा का द्वार खोल दिया। यह कोई साधारण काम नहीं था और न ही उतना आसान था। अपने द्वारा सोचे गए परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता को उन्होंने पहले ही पहचान लिया था। डॉ. वारसी ने पटना में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की। इस संस्था ने अनगिनत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। इसके कारण बिहार में शिक्षा की नयी धारा प्रवाहित होने लगी। शिक्षा के प्रति डॉ. वारसी का समर्पण यहीं नहीं रुका। वह मुस्लिम समुदाय के भीतर शैक्षिक सुधारों की वकालत करते हुए बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के सदस्य बने। उन्होंने ज्ञान के माध्यम से सशक्तिकरण के संदेश को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। आज जो बिहारी समाज शिक्षा के मामले में अन्य किसी प्रांत की तुलना में मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसकी भूमिका डॉ. वारसी जैसे समाज सुधारकों की ही देन है।

डॉ. वारसी की शैक्षिक पहल का प्रभाव बिहार की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनकी कहानी, उनके जैसे अनगिनत अन्य लोगों बारे में दर्शाती है कि कट्टरपंथ को रोकने में शिक्षा एक शक्तिशाली हथियार साबित हो सकता है। शिक्षा व्यक्तियों को आलोचनात्मक सोच और अभिनव कौशल से सुसज्जित करती है तथा सहिष्णुता को बढ़ावा देती है। शिक्षा रचनात्मक संवाद को प्रोत्साहित करती है। डॉ. वारसी जैसे शिक्षित व्यक्ति चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति कम संवेदनशील होते हैं क्योंकि उनके पास सवाल पूछने, तर्क करने की शक्ति विकसित हो जाती है। साथ ही मानवीय दृष्टि को बढ़ावा देने वाली समझ विकसित हो जाती है। शिक्षा गलत धारणाओं को हतोत्साहित कर देती है। गैर जरूरी रूढ़ियों के खिलाफ खड़े होने की शक्ति प्रदान करती है। विभिन्न सांस्कृतिक समूहों के बीच दूरियों को पाटने का साहिस प्रदान करती है। गलतफहमियां दूर करती हैं और सद्भाव को बढ़ावा देती हैं। डॉ. प्रोफेसर कासिम अहसन वारसी की जीवन यात्रा, मुस्लिम समुदाय के भीतर शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति को रेखांकित करती है। शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें कट्टरपंथ से बचाकर नयी जीवन दृष्टि देती है।

परमात्मा को जाने बिना किसी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता

शिमला। विश्व मानवता पार्लियामेंट के अध्यक्ष और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के संस्थापक मास्टर ऑफ एन्सिएंट साइंस परम पूज्य

महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी

ने अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के बाद अब अरब देशो में भी आदि सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। यूएईके अबू धाबी में विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन और मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स द्वारा 6–7 नवंबर 2023 को आयोजित इंटरनेशनल PRE-COP28 इंटरफेथ स्टेटमेन्ट सम्मेलन में परम पूज्य महाबह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी भारत के विशेष प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुये। अबूधाबी इंटरफेथ स्टेटमेंट सम्मेलन अनेक जवलन समस्याएं जैसे रोग कीटाणु महामारी युद्ध मन शरीर के तनाव आदि पर धर्म गुरुओं के सहयोग से समाधान निकालने का प्रयास था। सम्मेलन में विश्व के विशिष्ट लोगों ने कहा कि किस प्रकार विश्व स्तर पर समस्याएं बढ़ रही है और सभी ने एकमत से स्वीकार किया कि इसका व्यवहारिक भौतिक व मेडिकल जगत में कोई समाधान नहीं है। परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया की सारी समस्याओं और मानवता के मतभेद का मूल कारण अज्ञानता से है। महाब्रह्मर्षि ने कहा सभी धर्म ग्रंथो में विदित है कि हमारे हजारों लाखों पर्दे हैं जिन में मूल है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन बुद्धि और अहंकार के परदे हैं। इनके हटने के बाद ही परमात्मा की रहमत प्रत्यक्ष होती है। ऐसा सभी धर्म ग्रंथो में लिखा है। लाखों वायरल फंगल हैं। यह भी परदे हैं। आयुर्वेद में वर्णित है की पांच तत्वों के संतुलन से ही शरीर निरोगी होता है यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। इसे मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। इस ज्ञान के बारे में कोई बोलकर नहीं बता सकता। यह ज्ञान ज्ञाता–तत्ववेता–बाखबर द्वारा ही मिलता है। कुरान–ए–पाक में दिया है कि यह सारा ज्ञान पहले दिया जा चुका है। यही ज्ञान वेदों, उपनिषद, बाइबिल, श्री गुरुग्रंथ साहिब जी सभी में विदित है। भगवान श्री कृष्ण जी से जब पूछा गया की गीता के ज्ञान के बारे में दोबारा बतायें तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उस समय मै योग युक्त था, अब मैं वह ज्ञान दोबारा नहीं दे सकता। महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने वहां उपस्थित सभागणों को अवधान महायोग कराकर तीन मिनट में सबकी समस्याओं का समाधान किया।

अवधान महायोग कर पूरी दुनिया के धर्मगुरु, डॉक्टर, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ भावविभोर होकर प्रसन्नता से भर गये उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में पहली बार परमात्मा की एकरूपता का अनुभव किया। अनेक इस्लामिक धर्म गुरुओं ने हर्ष उल्लास से कहा कि उन्हें खुदा की रहमत का साक्षात्कार हुआ। एंजेल गेब्रियल ने ही मोहम्मद साहब जी को कुरान–ए–पाक का ज्ञान दिया और कुरान–ए–पाक में स्पष्ट वर्णित है कि अल्लाह से बात करना और अल्लाह का साक्षातकार करना तब तक संभव नहीं है जब तक पर परदे न हटे या रसूल से अल्लाह का ज्ञान न मिले। हमारी इंद्रियों पर अज्ञान के करोड़ों परदे हैं। महाब्रह्मर्षि जी ने अवधान महायोग के माध्यम से सभी के पर्दे हटाये। यह देखकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के प्रेसिडेंट अल जबेर ने कहा कि महा ब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी महान हैं और इन जैसे महान धर्माचार्य वैश्विक स्तर की समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने कहा कि परमात्मा को जाने बिना किसी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि परमात्मा की एकरूपता को जान लिया तो विश्व से धर्म के नाम पर होने वाले सभी विवाद समाप्त हो जाएंगे और दुनिया विश्व शांति की ओर अग्रसर हो जायेगी। सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने श्री कुमार स्वामी जी के साथ व्यक्तिगत भेंट की और उनसे सनातन संस्कृति के वह अद्भुत रहस्य ग्रहण किये जिनसे विश्व के करोड़ों लोगों का जीवन बदल चुका है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता को लेकर पूरे देश में खुशी की लहर है। पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ गोविंद जी ने महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को बधाई दी और कहा कि अरब देशों में भारतीय संस्कृति को मान्यता दिलाने के लिये आपने जो अविस्मरणीय कार्य किया है वह कोई धर्माचार्य नहीं कर सकता है। अगर यह घटना वर्ष 1947 से पूर्व घटित हुई होती तो भारत व अन्य देशों के युद्ध समाप्त हो जाते और अभी भी हो जाएंगे। भारत के अनेक महामंडलेश्वरों, संतो, धर्मगुरुओं और राजनेताओं ने भी महब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को बधाई दी। सम्मेलन के अंत में 28 धर्मगुरु ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए हस्ताक्षर कर संकल्प किया कि विश्व की ज्वलंत समस्याओं का समाधान अध्यात्म के द्वारा किया जाना चाहिए। श्री कुमार स्वामी जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आयोजित समिति के सदस्यों ने महाब्रह्मर्षि जी के हाथों यूएई के राष्ट्रीय वृक्ष **Ghaf Tree** (शान्ति और स्थिरता का प्रतीक) पर अपर्ण का पुनित कार्य करते हुये सम्मेलन का समापन किया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

शिमला। प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की थी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ऑन–स्पॉट सेवाओं के एक भाग के रूप में ग्राम पंचायतों में आईईसी वैन के रुकने के स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

26 नवंबर 2023 तक, 995 ग्राम पंचायतों में 5,470 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 7,82,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई। जिसमें पंजाब के रूपनगर, ओडिशा के सुंदरगढ़,

हिमाचल प्रदेश के चंबा, आंध्र प्रदेश के कृष्णा, महाराष्ट के नासिक, असम के तिनसुकिया से लोग शामिल हुये।

स्वास्थ्य शिविरों में आयुष्मान भारत **–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी– पीएमजेएवाई):** विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए एमओएचएफडब्ल्यू की प्रमुख योजना के तहत, आयुष्मान ऐप का उपयोग करके आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं और लाभार्थियों को भौतिक कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। बारहवें दिन के अंत तक शिविरों में 9,35,970 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाये गये और 1,07,000 से अधिक भौतिक कार्ड वितरित किये गये।

क्षय रोग (टीबी): टीबी रोगियों के लक्षणों, बलगम परीक्षण और जहां भी उपलब्ध हो, एनएएटी मशीनों का उपयोग करके जांच की जा रही है। जिन मामलों में टीबी होने का संदेह होता है उन्हें उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रेफर किया जाता है। बारहवें दिन के अंत तक, 1,95,000 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिनमें से 19,500 से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भेजा गया।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमए) के तहत, टीबी से पीड़ित मरीजों को निक्षय मित्रों से सहायता प्राप्त करने के लिए सहमति ली जा रही है। निक्षय मित्र बनने के इच्छुक प्रतिभागियों का वहीं के वहीं (ऑन–स्पॉट) पंजीकरण भी कराया जा रहा है। बारहवें दिन के अंत तक, 11,500 से अधिक रोगियों ने पीएमटीबीएमबीए के तहत सहमति दी और 5,500 से अधिक नए निक्षय मित्र पंजीकृत किए गए।

निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के तहत, टीबी रोगियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से मौद्रिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए लंबित लाभार्थियों के बैंक खाते का विवरण लिया जा रहा है और उनके खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है। बारहवें दिन के अंत तक ऐसे 3,371 लाभार्थियों का विवरण एकत्र किया गया।

सिकल सेल रोग: प्रमुख जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में, एससीडी के लिए प्वाइंट ऑफ केयर (पीओसी) परीक्षणों के माध्यम से या घुलनशीलता परीक्षण के माध्यम से सिकल सेल रोग (एससीडी) का पता लगाने के लिए पात्र आबादी (40 वर्ष तक की आयु) की जांच की जा रही है। जिन लोगों में रोग का पता चलता है उन्हें इलाज के लिए उच्च केंद्रों पर भेजा जा रहा है। बारहवें दिन के अंत तक 54,750 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिनमें से 2,930 लोगों में बीमारी के लक्षण पाये गये और उन्हें उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भेजा गया।

गैर संचारी रोग (एनसीडी): उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए पात्र आबादी (30 वर्ष और उससे अधिक) की जांच की जा रही है और बीमारी के लक्षण होने के संदेह वाले लोगों को उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जा रहा है। बारहवें दिन के अंत तक, लगभग 5,51,000 लोगों की उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच की गई। 31,000 से अधिक लोगों में उच्च रक्तचाप के और 24,000 से अधिक लोगों में मधुमेह के लक्षण दिखे और 48,500 से अधिक लोगों को उच्च सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में भेजा गया।

जीएसटी राजस्व वृद्धि के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के महत्वाकांक्षी प्रयास

शिमला। प्रदेश सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और आर्थिक सेहत में सुधार के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के लिए भी हर क्षेत्र में नई पहल की गई हैं।

व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ कार्यरत प्रदेश सरकार ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं।

देशभर में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रशासन के लिए धोखाधड़ी से पंजीकरण रोकना सबसे बड़ी चुनौती बना है। जीएसटी प्रणाली में धोखाधड़ी से किए गए पंजीकरण से सरकारी राजस्व को भारी नुकसान होता है।

इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार के राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने भी जीएसटी राजस्व की सुरक्षा और वृद्धि के लिए कई पहल की हैं।

जीएसटी प्रणाली में धोखेबाजों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए विभाग ने पंजीकरण आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बाद मैन्युअल मोड में जीएसटी पंजीकरण के शत–प्रतिशत अनुमोदन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, विभाग जोखिमपूर्ण समझे जाने वाले पंजीकरणकर्ताओं के भौतिक सत्यापन के लिए भी उचित उपाय कर रहा है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग कर चोरी की पहचान करने और उस पर कारवाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके दृष्टिगत विभाग द्वारा केंद्रीय कर अधिकारियों के साथ भी समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। धोखाधड़ी करने वाले करदाताओं का शीघ्र पता लगाने के लिए विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय में पुख्ता व्यवस्था स्थापित की जा रही है ताकि कर चोरी के मामलों को प्रथम चरण में ही रोके जाने के साथ ही राजस्व हानि को कम किया जा सके।

स्वस्थ कार्य वातावरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए विभाग ने कर चोरी के मामलों का शीघ्र पता लगाने, कर प्रशासकों की क्षमता निर्माण, राजस्व वृद्धि की गुंजाइश वाले क्षेत्रों की पहचान व क्षेत्र संरचनाओं के प्रदर्शन की निगरानी में सुधार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत करने के लिए जीएसटी के तहत राजस्व वृद्धि के लिए नई पहल की हैं।

जीएसटी मुआवजे के घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा जीएसटी राजस्व वृद्धि परियोजना आरम्भ की गई है। इस परियोजना से सामान्य राजस्व वृद्धि के अलावा लगभग 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व वृद्धि अपेक्षित है।

प्रदेश सरकार कर अनुपालना में गुणात्मक सुधार लाने के लिए भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसके दृष्टिगत व्यापारियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने सद्भावना योजना–2023 शुरू की है। इसके तहत सामान्य बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर और प्रवेश शुल्क इत्यादि अधिनियमों के तहत लम्बित मामलों का निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है।

कर चोरी मामलों पर अंकुश लगाने के साथ–साथ विभाग के अधिकारियों की दक्षता और क्षमता बढ़ौतरी के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

इसके साथ–साथ राज्य कर एवं आबकारी विभाग राजस्व वृद्धि के लिए जीएसटी परिषद के साथ भी विभिन्न मामलों को निरंतर उठाता रहा है। उपभोक्ताओं और अन्य अपंजीकृतों द्वारा 50 हजार रुपये से अधिक की खरीद के आपूर्ति स्थान को रिकार्ड करने के लिए जीएसटी परिषद की मंजूरी प्राप्त करने में भी विभाग सफल रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों से राजस्व वृद्धि में मदद मिल रही है। इससे प्रदेश के विकास और प्रगति मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।

संविधान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने डॉ.अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पाजंलि अर्पित की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संविधान दिवस के अवसर पर शिमला स्थित, चौड़ा मैदान में भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा पर प्रदेशवासियों की ओर से पुष्पाजंलि अर्पित की।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, विधायक हरीश जनारथा व रवि ठाकुर, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान, उप-महापौर उमा कौशल, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर, राष्ट्रीय बचत राज्य सलाहकार बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रकाश चंद करड़, नगर निगम शिमला के पार्षदगण और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पुष्पाजंलि अर्पित की।

इस मौके पर कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति विभाग व डॉ. भीम राव अम्बेडकर वेल्फेयर सोसायटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी वर्ष से संविधान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉ. भीम राव अम्बेडकर समाज सुधारक और प्रख्यात विद्वान थे। उनके आदर्श सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। शिक्षा और समाज की प्रगति के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे।

मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित लोगों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि डॉ. भीम राव अंबेडकर सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत हैं। संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए संविधान दिवस आयोजित किया जाता है। हमारे संविधान ने नागरिकों को गरिमा और एकता का संदेश दिया है।

समारोह में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के कलाकारों ने देशभक्ति पर आधारित गीतों की प्रस्तुति दी।

सरकार की नीतियों-कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने में सचिवालय कर्मचारियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारी, महिला तथा किसान हितैषी सरकार है। प्रदेश में वर्तमान सरकार के गठन के बाद जनकल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए गए। प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों के प्रति मानवीय एवं सामाजिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके लिए पुरानी पैंशन योजना को लागू किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस लागू करना संवेदनशील सरकार का संवेदनशील फैसला है तथा यह निर्णय किसी राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों और कर्मचारियों की राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका है। लम्बे समय तक सेवाएं देने के उपरांत यदि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत निश्चित आय का साधन न हो तो वे सम्मान से जीवनयापन नहीं कर सकते हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सचिवालय मिनी हिमाचल है जहां सभी ज़िलों की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में कार्यरत सभी कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं तथा उन्हें हिमाचल की जनता की आशाओं के अनुरूप कार्य करना होगा।

उन्होंने कहा कि आने वाले एक वर्ष में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं लागू करने जा रही है, जिसमें सचिवालय कर्मचारी पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी तथा आने वाले दो-तीन माह में महंगाई भत्ते की किश्त पर भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही सप्ताह में पांच कार्यदिवस करने की मांग पर विचार किया जाएगा।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। संजीव शर्मा ने प्रधान, कमल कृष्ण शर्मा ने महासचिव, रमन शर्मा ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महेन्द्र सिंह ने उपाध्यक्ष, हुकम सिंह ने संयुक्त सचिव, रामपाल शर्मा ने कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के नौ सदस्यों ने शपथ ग्रहण की।

हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

नगर निगम चुनाव में विधायकों को वोटिंग अधिकार देना सही: नरेश चौहान

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव में विधायकों को चुनाव का अधिकार देना सरकार का सही फैसला है । यह बात मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार(मीडिया)नरेश चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि विधायकों की मांग पर स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में प्रदेश सरकार का यह एक सही फैसला है।

नरेश चौहान ने कहा कि लंबे समय से विधायकों की ओर से मांग की जा रही थी कि विधायकों को मत देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार ने उनकी इस मांग पर गौर करते हुए विधायकों को नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया है. उन्होंने कहा इससे लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में भी नगर निगम महापौर उप महापौर के चुनाव में सांसद भी वोट करते है ऐसे में हिमाचल में सरकार ने विधायको को वोटिंग अधिकार देना गलत नही है।

प्रदेश भाजपा द्वारा वर्तमान सरकार पर 11 महीने के कार्यकाल में 10,000 करोड़ से अधिक ऋण लेने के आरोप पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि डबल इंजन सरकार होने का दावा करने वाली पूर्व की भाजपा सरकार ने ही प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाया। उन्होंने 10,000 करोड़ के कर्ज लेने के भाजपा के आरोप को सिरे से खारिज किया। नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार पर 10 हजार करोड़ रूपये का ऋण लेने का आरोप लगाने वाली पूर्व की जयराम सरकार ने खुद एक साल में 15000 करोड़ तक का ऋण ले लिया था।

युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष प्रयास

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं इसलिए युवा और भावी मतदाताओं की पहचान कर उनके पंजीकरण में सुधार के लिए विशेष प्रयास करने के उद्देश्य से प्रत्येक 68 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक समर्पित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की गई है। युवा/भावी मतदाताओं, विशेष रूप से 18-19 आयु वर्ग में अधिक से अधिक पंजीकरण के लिए शैक्षणिक संस्थानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने बताया कि समर्पित 68 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर संभावित मतदाताओं के पंजीकरण के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों के चुनावी साक्षरता क्लब के साथ नियमित बैठकें करेंगे और उन्हें नामांकन की प्रक्रिया और पंजीकरण के लिए आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा के बारे में जागरूक करेंगे।

उन्होंने बताया कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों में पुनरीक्षण गतिविधियों के दौरान विशेष शिविरों का आयोजन करेंगे, ताकि मतदाताओं की पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें एन.वी.एस.पी. वी.एच.ए./ वी.पी. आदि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए अग्रिम दावे दायर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जबकि ऐसे मामलों में जहां इंटरनेट की पहुंच या अन्य किसी कारण से ऑनलाइन आवेदन जमा करना संभव नहीं है, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवेदन को भरने में आवेदक की सहायता करेंगे। ऑफलाइन प्रपत्र-6 में प्राप्त आवेदनों को डिजिटलीकृत और आगे की आवश्यक कारवाई के लिए ई. आर.ओ. नेट के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक समर्पित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को लॉग-इन आईडी प्रदान की जाएगी।

समर्पित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्राप्त प्रारूप का संस्थानवार तिमाही डाटा बनाए रखेंगे। इससे पंजीकरण के प्रतिशत में सुधार करने और रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

जाइका करेगा स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग

शिमला/शैल। जाइका वानिकी परियोजना अब स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों की ब्रांडिंग करेगा। 10वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में यह निर्णय लिया। प्रधान सचिव वन एवं गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन डा. अमनदीप गर्ग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। इस महत्वपूर्ण बैठक में पिछले छह महीने के विकास कार्यों पर मंथन किया गया और 20 के करीब नए एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव वन डा. अमनदीप गर्ग ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना के तहत हो रहे विकासात्मक कार्यों में और तेजी लाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल एवं मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि कुल्लू में जाइका परियोजना के तहत 106 स्वयं सहायता समूह हैं, जो हैंडलूम प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इन उत्पादों की ब्रांडिंग जाइका खुद करेगा। इसके अलावा हिमाचल में विलुप्त हो रहे उतक संवर्धन यानी टिशू कल्चर प्रजातियों के पौधे जाइका की नर्सरियों में तैयार किए जाएंगे। बुरांश और भोजपत्र जैसे पौधे तैयार करने के लिए कार्य शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल तक प्रदेश में 46 हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण किया गया। इस साल 2 हजार हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य था जो रिकार्ड 23 सौ हेक्टेयर भूमि पर किया गया। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना के तहत सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की रिइम्बर्समेंट सौ प्रतिशत हो चुका है। उन्होंने कहा कि गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में जिन-जिन एजेंडे पर चर्चा की गई जिसमें से अधिकांश को मंजूरी भी दी गई। पीसीसीएफ एवं वन विभाग के मुखिया राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना पर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जाइका परियोजना के तहत अब तक कई उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, मधुमक्खी पालन, पत्तल व्यवसाय, मशरूम की खेती, हथकरघा एवं बुनकर समेत कई क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को आजीविका कमाने के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

हमीरपुर में खुलेगा बिजली बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय

शिमला/शैल।मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन

तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए 'पुनर्वास' कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 14 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की, जिनमें 122 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए। ऐसे परिवारों को कुल पहली किस्त के रूप में 3.66 करोड़ रुपए जारी किए गए।

मुख्यमंत्री ने जिला के दो बेघर परिवारों को भूमि के दस्तावेज सौंपे तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 555 मकानों की मरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्हें कुल 5.55 करोड़ की राशि जारी की गई। इसके अलावा उन्होंने प्रभावित 8 दुकानों और ढाबों मालिकों को भी एक-एक लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। उन्होंने क्षतिग्रस्त 622 गौशालाओं की मरम्मत के लिए 3.11 करोड़ रुपए, आपदा में अपना सामान गंवा चुके 71 परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की।

इसके अलावा आपदा के कारण जिला हमीरपुर में क्षतिग्रस्त हुई 1103 कनाल भूमि की एवज में 10 हजार रुपए प्रति बीघा की दर से कुल 55 लाख रुपए तथा 1760 कनाल भूमि पर किसानों की फसल को हुए नुकसान पर 4 हजार रुपए प्रति बीघा की दर से 35.20 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने 27 पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को 8 लाख रुपए की राशि जारी की।

मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में विद्युत बोर्ड का चीफ इंजीनियर कार्यालय खोलने तथा हमीरपुर शहर की बिजली की तारों को भूमिगत करने के लिए 20 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा करते हुए कहा कि एक वर्ष में शहर की बिजली की तारों को भूमिगत किया जाएगा। उन्होंने वर्षों से लम्बित बस स्टैंड के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 2 करोड़ रुपये प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेरी में तीन करोड़ रुपये की लागत से बागवानी विश्वविद्यालय के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व में 1100 करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। शराब के ठेकों की नीलामी से राज्य सरकार को 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हमीरपुर में जल्द ही राज्य चयन आयोग शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल स्टूडेंट योजना के तहत जिला हमीरपुर के 13 मेधावी विद्यार्थियों को टेबलेट भी प्रदान किए।

शिक्षा में किए जा रहे सुधारों में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्या समीक्षा केंद्र(वीएसके) का लोकार्पण किया। यह महत्वाकांक्षी योजना राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा और कान्वे जीनियस के सहयोग से आरम्भ की गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्विफ्ट चैट एआई (कृत्रिम मेधा)

द्वारा संचालित विद्या समीक्षा केंद्र हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों को प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित प्रणाली से सक्षम बनाएगा। शिक्षा में एआई प्रौद्योगिकी और सुशासन के एकीकरण के माध्यम से यह प्रणाली सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासकों को सही सामग्री और जानकारी से और सशक्त बनाएगी। उन्होंने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र सभी प्रमुख कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी में मदद करेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र, स्विफ्ट चैट पर संवादात्मक एआई चैटबाट की विविध श्रृंखला डिजिटल मित्र की तरह काम करेगी, जो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, शिक्षकों की सहायता और प्रशासकों के लिए मूल्यवान डेटा उपलब्ध करवाएगा। यह जिलों, खण्डों और स्कूलों के लिए डैशबोर्ड और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इससे विद्यार्थियों की प्रगति, शिक्षक प्रशिक्षण और समग्र स्कूल प्रदर्शन से सम्बंधित डेटा उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि वास्तविक समय में प्रतिक्रिया और सुधारात्मक सुझाव के आधार पर शिक्षक शिक्षण सम्बंधी रणनीतियों में बदलाव कर सकेंगे, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को सीखने के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना शिक्षकों की पहली जिम्मेदारी है। राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करना है, जहां सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी गौरवान्वित महसूस करें। राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा लर्निंग इत्यादि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पाठयक्रम शुरू किए हैं।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना को भी साकार करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शिक्षा क्षेत्र में राज्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा और विद्या समीक्षा केंद्र इस दिशा में मील पत्थर साबित होगा।

कान्वे जीनियस ग्रुप के अध्यक्ष शशांक पांडे ने कहा कि हिमाचल विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की दृष्टि से संवादी एआई को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य एडटेक को तेज, स्मार्ट और सरल बनाना है ताकि दुर्गम क्षेत्रों तक गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इससे पहले, सचिव शिक्षा राकेश कंवर ने परियोजना के बारे में जानकारी प्रदान की।

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

पोर्टमोर स्कूल के सभी क्लासरूम को स्मार्ट बनाने की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के लिए 5 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले छात्रावास का शिलान्यास किया और सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास में बदलने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन योजना के तहत टैबलेट प्रदान करने का शुभारम्भ किया और 16 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि टैबलेट प्राप्त करने वाले प्रदेश के कुल 10,540 विद्यार्थियों में से 7,520 बालिकाएं हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार की योजना बनाई जा रही है। अध्यापकों की कमी को दूर किया जा रहा है और अगले शैक्षणिक सत्र से शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 10 स्कूलों को राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर 5-5 स्कूलों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की स्मार्ट यूनिफार्म का फैसला एसएमसी और स्कूल प्रबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर और कक्षाओं में सुधार लाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों के सीखने के बेहतर अनुभव प्राप्त हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने जा रही है, जहां विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के 4000 अनाथ बच्चों को 'चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट' का दर्जा दिया, जिसके तहत उनकी देख-रेख, शिक्षा और आत्मनिर्भर बनाने का जिम्मा राज्य सरकार का कानूनी दायित्व है। उन्होंने कहा कि विशेष बच्चों को मुख्यधारा में लाने के लिए अगले बजट में एक योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेधावी छात्राओं को ई-स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार रुपये का अनुदान प्रदान कर रही है। सुविधाओं के अभाव में कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित न रहे इसके लिए राज्य सरकार ने डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू की है, जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार एडमिशन फीस की पहली किश्त उपायुक्त के माध्यम से प्रदान करेगी ताकि ऋण मिलने में देरी होने के कारण उसे एडमिशन से हाथ न धोना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दे रही है। बेटियों की शादी की आयु को बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है और कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सचिव स्तर का ग्रुप बनाया जा रहा है। इससे बेटियों को जीवन में आगे बढ़ने के और अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में राजनीति में भी उन्हें अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि रास्ते में जाते हुए कुछ छोटी बच्चियों ने उन्हें स्कूल आने का आग्रह किया और उनके अनुरोध पर ही वह इस कार्यक्रम में आए हैं। उन्होंने अपने छात्र व राजनीतिक जीवन के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और लग्न से निरंतर अपने ध्येय की ओर अग्रसर रहने से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए स्कूल को एक लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि यह विद्यालय प्रदेश के उत्कृष्ट विद्यालयों में से एक है। इसका समृद्ध इतिहास है तथा प्रदेश भर से छात्राएं इस स्कूल में पढ़ने के लिए आती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध करवा रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पोर्टमोर स्कूल में कन्या छात्रावास के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने पुरस्कार पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

विधायक हरीश जनारथा ने छात्रावास की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे यहां पढ़ने वाली छात्राओं को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे।

विद्यालय की प्रधानाचार्या ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत किया और स्कूल की उपलब्धियों की जानकारी दी।

उद्योग मंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का दौरा किया

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न स्टॉलों

से फीडबैक लिया तथा हिमाचल मंडप प्रबन्धन की सराहना करते हुए कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास, नवोन्मेषी प्रयासों, पहल तथा समृद्ध कला एवं संस्कृति को देश के सामने प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

उद्योग मंत्री ने उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा अन्य राज्यों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन एवं हस्तशिल्पियों से संवाद भी किया। उन्होंने विभिन्न उद्यमियों से हिमाचल में पर्यटन, उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी किया।

इस अवसर पर अवगत करवाया गया कि हिमाचल मंडप में अभी तक लगभग 80 हजार आगंतुक अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या क्षेत्रीय असन्तुलन सरकार के लिये चुनावों में भारी पड़ेगा?

भाजपा की आक्रामकता पर कांग्रेस की चुप्पी सवालों में क्या सुक्खू भविष्य की राजनीति देख रहे हैं?

शिमला/शैल। भाजपा कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों में दी गारंटीयों का पूरा करने में सुक्खू सरकार द्वारा अब तक कोई भी प्रभावी कदम न उठाये जाने को लेकर लगातार आक्रामक होती जा रही है। भाजपा जितना आक्रमक होती जा रही है उसी अनुपात में कांग्रेस का जवाब कमजोर होता जा रहा है। बल्कि सुक्खू सरकार पर क्षेत्रीय असन्तुलन का आरोप ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। मंत्रिमण्डल में चले आ रहे तीनों खाली पदों को न भर पाना अब सुक्खू सरकार का नकारात्मक पक्ष गिना जाने लगा है। इस समय कांगड़ा से एक ही मंत्री का सरकार में होना शान्ता जैसे वरिष्ठतम नेता को यह कहने पर मजबूर कर गया है कि कांगड़ा को मंत्री नहीं मुख्यमंत्री के लिये लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि प्रदेश में सरकार बनाने का फैसला सबसे बड़ा जिला होने के नाते कांगड़ा ही करता है। शान्ता के इस सुझाव का कांगड़ा के राजनेताओं पर कितना और क्या असर पड़ता है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन शान्ता के इस उपदेश के बाद ही कांगड़ा से एकमात्र मंत्री चंद्र कुमार का मंत्रिमण्डल विस्तार को लेकर ब्यान आया है। इसी उपदेश के बाद ही मुख्यमंत्री का भी विस्तार को लेकर ब्यान आया है। इन ब्यानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह क्षेत्रीय असन्तुलन का आरोप लोकसभा चुनावों में अवश्य असर दिखायेगा।

क्षेत्रीय असन्तुलन तो मंत्रिमण्डल से बाहर हुई राजनीतिक ताजपोशीयों में भी पूरी नग्नता के साथ प्रदेश के सामने आ गया है। इस समय मुख्यमंत्री की सहायता के लिये सलाहकारों विशेष कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्तियों में करीब 90% की हिस्सेदारी अकेले जिला शिमला की हो गयी है। इसी बड़ी हिस्सेदारी के कारण ही सुक्खू सरकार को कुछ विश्लेष्कों ने मित्रों की सरकार का उपनाम दे दिया है। इस उपनाम का व्यवहारिकता में जवाब देने का साहस किसी कार्यकर्ता में नहीं हो पा रहा है। बल्कि कुछ विश्लेष्क मुख्यमंत्री की कार्यशैली का इस तरह विश्लेष्ण कर रहे है कि सुक्खू अपनी पूरी राजनीतिक कुशलता के साथ मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गये हैं। मुख्यमंत्रे बनने के बाद शिमला नगर निगम के चुनाव आये और उसमें भी शिमला वासियों को कुछ वायदे करके जिनमें एटिक को रिहाईसी बनाना और बेसमैन्ट को खोलना आदि शामिल थे के सहारे यह चुनाव भी जीत गये। अब लोकसभा चुनावों की हार जीत में तो पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों की ही भूमिका रहेगी। फिर लोकसभा चुनाव तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में भी हारे हैं। विधानसभा में कोई भी मुख्यमंत्री स्व.वीरभद्र सिंह से लेकर शान्ता, धूमल और जयराम तक कोई रिपीट नहीं कर पाया है। इसमें सुक्खू के नाम कोई दोष नहीं आयेगा। लेकिन इस दौरान जिन मित्रों को वह राजनीतिक लाभ दे पायेंगे वह पार्टी के अन्दर उनका एक प्रभावी तबका बन जायेगा। इसलिये सुक्खू को लेकर जो यह धारणा फैलाई जा रही है कि वह किसी की नहीं सुनते और अपनी ही मर्जी करते हैं इसके पीछे पार्टी के अन्दर आने वाले वक्त के लिये अपना एक स्थाई वर्ग खड़ा करना है।

इस समय कांग्रेस गारंटीयां पूरी नहीं कर पायी है इस आरोप का एक बड़ा हिस्सा पिछले दिनों आयी आपदा में छुप जाता है। जहां तक लोकसभा चुनावों का प्रश्न है उसके लिये सुक्खू की राजनीति को समझने वालों के मुताबिक वह कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला से मंत्रियों या वरिष्ठ विधायकों को चुनावी उम्मीदवार बनवाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सुक्खू की अस्वस्थता के दौरान यही लोग महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। ऐसे में लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय असन्तुलन और आर्थिक कठिनाइयों का यदि सरकार जवाब न दे पायी तो यह चुनाव जीत पाना कठिन हो जायेगा।

सुक्खू सरकार ने दिल्ली में तैनात किया सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर

आउटसोर्स के माध्यम से की गयी नियुक्ति से सरकार की नीयत और नीति सवालों में

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने पिछले दिनों कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाले राजा अवस्थी को दिल्ली में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से की गयी है। आउटसोर्स की प्रक्रिया को प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने अंजाम दिया है। निगम ने राजा अवस्थी का नाम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को उसकी सहमति के लिये भेजा। विभाग ने इसे स्वीकार करके राजा अवस्थी को दिल्ली में यह नियुक्ति दे दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन को राजा अवस्थी का नाम शिमला की एक आउटसोर्स कंपनी द्वारा प्रेषित किया गया है। इस नियुक्ति से यह इंगित होता है कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कुछ कार्यो को सरकार आउटसोर्स कंपनियों को सौंपना चाहती है। जिसमें दिल्ली में सोशल मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना भी शामिल है। वैसे दिल्ली में विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय भी कार्यरत है। लेकिन सरकार ने विभाग को सक्षम न मानकर दिल्ली में यह काम एक आउटसोर्स कंपनी को दिया है। सुक्खू सरकार ने सत्ता में आने के बाद आउटसोर्स के माध्यम से कोविड काल में स्वास्थ्य विभाग में रखे गये 1800 से अधिक कर्मचारियों को बाहर निकाला भी है। इस निष्कासन से उठे विवाद के बाद आउटसोर्स योजना पर कुछ विचार विमर्श भी हुआ है। राजा अवस्थी की नियुक्ति से आउटसोर्स की प्रासंगिकता तो प्रमाणित हो जाती है और यही सवाल खड़ा होता है कि इसके माध्यम से अपने ही लोगों को भर्ती करने का साधन बनाया जाये। आउटसोर्स के माध्यम से रखें कर्मियों को भी सरकार में भर्ती करने का प्रावधान रखा जाये। इस समय जो 35000 के करीब आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये कर्मचारी है उनके भविष्य को लेकर भी सरकार को सोचना चाहिये। इस नियुक्ति की चयन प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के साथ सरकार की मीडिया पॉलिसी पर उसकी नीयत और नीति दोनों ही अलग से प्रशनित हो गये हैं। दिल्ली में सोशल मीडिया के लिये कोआर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार सोशल मीडिया मंचों की भूमिका और प्रासंगिकता दोनों को स्वीकार करती है। दिल्ली स्थित सोशल मीडिया मंचों तक सरकार का प्रश्न रखना और उसे प्रचारित प्रसारित करवाने की जिम्मेदारी इस सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की होगी। इस सरकार का पक्ष दिल्ली स्थित हाईकमान तक तो पहुंच जायेगा। लेकिन क्या वही पक्ष प्रदेश की जनता के सामने उसी क्लेवर में आ पायेगा और जनता उस पर विश्वास कर पायेगी? क्योंकि प्रदेश की जनता के सामने तो सरकार का व्यवहारिक पक्ष यथास्थिति मौजूद रहेगा। फिर शिमला स्थित मीडिया के कुछ वर्ग को जिस तरह सरकार ने उत्पीड़ित करना शुरू किया हुआ है उसके परिदृश्य में सरकार कुछ समय के लिये हाईकमान को तो प्रभावित कर लेगी परन्तु प्रदेश की जनता के सामने उसकी स्थिति और हास्यस्पद हो जायेगी। दिल्ली में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर बिठाने से सरकार स्वत: ही एक अन्तर विरोध का शिकार हो गयी है।

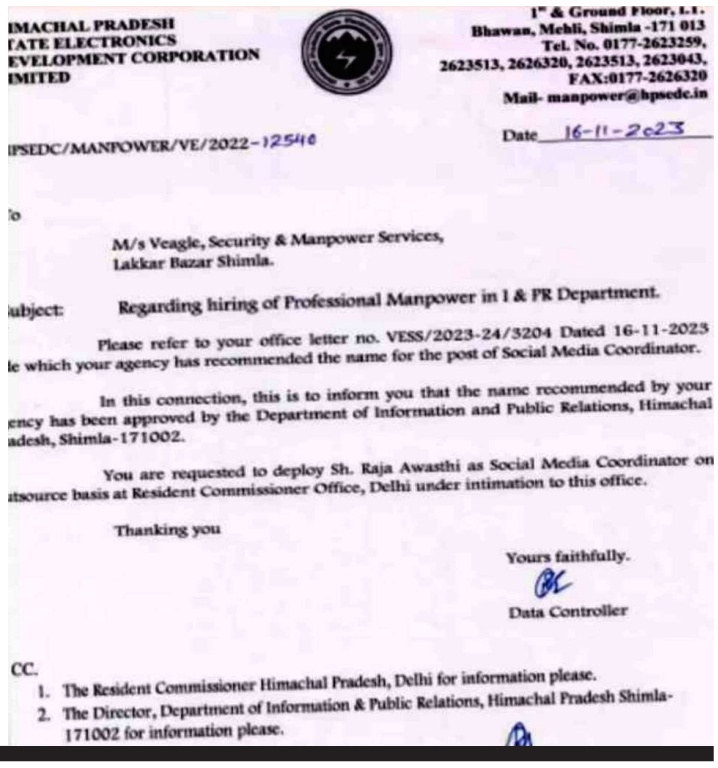

IMACHAL PRADESH
TATE ELECTRONICS
EVELOPMENT CORPORATION
IMITED

1st & Ground Floor, I.T.
Bhawan, Mehli, Shimla -171 013
Tel. No. 0177-2623259,
2623513, 2626320, 2623513, 2623043,
FAX:0177-2626320
Mail- manpower@hpsedc.in

IPSEDC/MANPOWER/VE/2022-12540

Date 16-11-2023

To

M/s Veagle, Security & Manpower Services,
Lakkar Bazar Shimla.

ubject: Regarding hiring of Professional Manpower in I & PR Department.

Please refer to your office letter no. VESS/2023-24/3204 Dated 16-11-2023
le which your agency has recommended the name for the post of Social Media Coordinator.

In this connection, this is to inform you that the name recommended by your
ency has been approved by the Department of Information and Public Relations, Himachal
adesh, Shimla-171002.

You are requested to deploy Sh. Raja Awasthi as Social Media Coordinator on
tsource basis at Resident Commissioner Office, Delhi under intimation to this office.

Thanking you

Yours faithfully.

Data Controller

CC.
1. The Resident Commissioner Himachal Pradesh, Delhi for information please.
2. The Director, Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh Shimla-171002 for information please.